ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of the Press briefing — Held at 1400 Hours 19.08.2014

Shri Anand Sharma addressed the media today.

श्री आनन्द शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बातें कहीं जिन पर अपनी प्रतिक्रिया देना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो 50 के दशक में भारत देश के अन्दर एक नियोजित ढ़ंग से विकास का कार्यक्रम चल रहा था–पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उस पर एक गहरा आघात किया है। प्रधानमंत्री का यह कहना कि देश में योजना आयोग की आवश्यकता नहीं है उसके पीछे सोच है जो किसी की समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि संघीय प्रणाली को देखते हुए राज्यों की भूमिका अहम हो जाती है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारी संघीय प्रणाली के अन्दर योजना आयोग और राज्य मिलकर काम करते हैं। योजना आयोग का काम केवल योजना बनाना नहीं था, बल्कि उनकी प्रस्तावना लेना–राज्यों के सुझाव लेना, उनसे चर्चा करना, उनकी प्राथमिकता देखना और उसके बाद सरकार से उस पर चर्चा करना। नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफी बात कही है इससे संघीय ढ़ांचा मजबूत नहीं होता, व्यवस्था मजबूत नहीं होती, उन्होंने लाल किले से घोषणा की है। बेहतर यह होता अगर वे यह बताते कि यूपीए सरकार में कई संशोधन हुए योजना आयोग में restructuring बात हुई। मार्च महीने में उस समय में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो परिस्थितियां हैं उनको मद्देनजर रख के योजना आयोग को भी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने पन्द्रह पेज का एक नोट इस विषय पर बनाया था, उसमें यह भी बताया गया था कि राज्यों से किस तरह ताल–मेल करना यह 15 पेज का नोट दिया था। उस नोट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि उस नोट को देश के सामने रखें। अगर उनकी सोच अलग है, उस नोट में संशोधन लाएं। और संघीय व्यवस्था का सम्मान करते हुए उनको सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी सोच से अवगत कराना चाहिए था क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। और National Development Council की मीटिंग बुलानी चाहिए थी सब राज्यों के सुझाव आने के बाद, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज कुछ समय पहले उन्होंने कुछ ट्विट किया है लोगों से सुझाव मांगे थे। अगर उनके पास कोई तस्वीर नहीं है, कोई रूपरेखा

नहीं है, तो यह घोषणा कैसे हुई। योजना आयोग कोई सरकारी विभाग नहीं है। कांग्रेस के हरिपुर के महाधिवेशन में 1938 यह निर्णय हुआ था कि स्वतंत्र भारत में योजना आयोग बनेगा। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय देश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है अभी इस पंचवर्षीय योजना का आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। उस समय इतना बड़ा फैसला करना कि भविष्य में किस तरह का होगा, किसी को यह स्पष्ट नहीं था। कभी कहा जाता है कि एक Think Tank बन जाएगा। सुझाव देने का काम योजना आयोग हमेशा करता रहा है। और योजना आयोग ही वित्त मंत्रालय से बात करके राज्यों को और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनका हर वर्ष का क्या बजट होना चाहिए, उसके लिए उनको क्या धन राशि देनी चाहिए, यह कार्यप्रणाली योजना आयोग की थी। और बड़े पैमाने पर जो पीपीपी योजनाएं हैं, चाहे वो हाईवेज़ की हैं, पोर्टस की हैं, पॉवर प्रोजक्ट हैं, वो भी योजना आयोग राज्यों से और वित्त या संबंधित मंत्रालयों से मिलकर करता है। योजना आयोग ने यूपीए–1 और 2 में काफी लचीलापन लाया था। इसीलिए मैंने एक पन्द्रह पेज के नोट का जिक्र किया है। इसका नरेंद्र मोदी जी ने कोई जिक्र नहीं किया और ना ही सरकार ने किया है जिसमें राज्यों को और भी स्वतंत्रता दे दी गई थी केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं पर उनको कार्यान्वित करने में।

Shri Anand Sharma said the decision of the Prime Minister and the announcement of the Prime Minister is a kneejerk half baked announcement from the ramparts of the Red Fort. While claiming that he is in favour of consultations and strengthening the federal structure by giving more space and role to the states of the Union of India, he has exactly done the opposite. It is arbitrary, there was no consultation with the states and none of the CMs were ever informed. It would have been proper for the Prime Minister first to write to all the CMs, take their views on board before taking such a major decision. This is a body blow to the federal structure. It is not strengthening the federal structure. Only the National Development Council is the right body and the forum in which CMs are Members and also the senior Ministers and the PM chairs it to take this decision. We feel that the government lacks clarity and confuse the country by tweeting to the people of India to give their suggestion. I do not know what institutional mechanism is to go through lakhs of millions of tweets and how can anybody sit and decide what would be the nature of planning. The Planning Commission has contributed through the 11 Five Year Plans and the 12th is currently under implementation in a planned development of the country where there is defined role of the states and also the budgetary allocations for all centrally sponsored and schemes and the building of the infrastructure. If any departure is to be made, the states have a key role to play. Secondly, what model - are hearing of Prime Minister Chairing the Think Tank to replace the Planning Commission or another structure which is not the bottoms up approach but a top

down approach like China have done away with the Planning Commission and converted it in to NDRC which is more driven by Politburo. We in India and I say with concern and responsibility that none is aware as to what made Shri Narendra Modi to do this. He owes it to the country. We are a democracy, cannot take such decisions in such a manner. We strongly object to this. Also it is equally important for me to mention that in doing so, Narendra Modi Ji and BJP government are showing antipathy and reversion to the builders of the Modern India Pt. Jawahar Lal Nehru who was not only the front ranking leader of India's freedom struggle having spent the maximum number of years in prison during the British colonial repression but he was also the builder of all modern Institutions like IITs, IIMs, Indian Institute of Science, Planning Commission, Indian Institute of National Space, Space Science and all other organizations whether you talk of Sahitya Kala Academies, the role of Pt. Jawahar Lal Nehru, it is his signature and if we have doubled these institutions during the UPA taking the No. of IITs from 7 to 16, and taking the No. of IIMs again from 6 to 13 and National Institute of Science from 1 to 5, National Institute of Design from 1 to 5 , it is done that was continuation respecting what Nehruvian vision was. This government also talks of the same but the PM did say that he does not believe in majority, he believes in consultation and consensus but there is a big difference between what he says and what he does.

और यह दोहरी जुबान में बात करते हैं। उन्होंने कभी पंड़ित जवाहर लाल नेहरू के योगदान को स्वीकार नहीं किया चाहे वो अंतरिक्ष का लांच देखने के लिए गए। अभी जितने दिन उनको आए हुए हैं, उतने दिन में ना तो अंतरिक्ष का लांच बना है, ना ही aircraft carrier अभी बनकर आया है, ना INS Kolkatta अभी बनी है। वर्षों से इस देश में काम हो रहे थे उस चीज को स्वीकार करने की शालीनता और मर्यादा देश के प्रधानमंत्री को होनी चाहिए यह अफसोस की बात है कि वो नहीं दिखां रहे। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आम सहमति से वो सरकार चलाएं और विपक्ष को और सभी पक्षों को साथ लेकर काम करें। उन्होंने संसद में चाहे वो नेता प्रतिपक्ष को स्वीकार करने की बात हो, उससे लेकर हर विषय पर सहमति तोड़ने की बात की है रजामंदी तोड़ने की बात की है, रजामंदी बनाने की उन्होंने कभी बात नहीं की इसी चीज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा 5Ts के बारे में और 3Ds के बारे में, संसद के अन्दर यह शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो उसमें टी का alphabet जरूर इस्तेमाल होता है। और 3 के बारे में भी यही है democracy, development and demography ऐसी कोई क्रांतिकारी सोच और दर्शन हमको उसमें नहीं दिखा था। अब वो Make for India, Made in India देश में निर्माण नीति यूपीए सरकार ने यह अक्टूबर 2011 को दे दी थी। जिसके तहत देश में निर्माण का योगदान हमारी जीडीपी में दस प्रतिशत बढ़ेगी। नए औद्योगिक शहर जो निर्माण को समर्पित हैं, National Investment Manufacturing Zones जिसे

राज्य और केंद्र मिलके बना रहे हैं, उसमें संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया था जिसमें जो सारी approvals है उसकी permission है, उसकी authority स्वयं होंगे NIMS। सोलह की घोषणा हो चुकी है, 50 किलोमीटर सबसे छोटा है। चार लांच कर दिए गए थे हमारे द्वारा, सबसे बड़ा 920 किलोमीटर का है गुजरात में। जापान एक बड़ा भागीदार है जापान की उसमें investment आ चुकी है जापान उसमें 50 बिलियन step loan के तहत ले के आया है। यह इसलिए बताना जरूरी है कि काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जापान भी जाएंगे तो कहेंगे कि मैं यह करके आ गया, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं यह सब बातें वो कहेंगे। एक US-2 plane के बारे में समाचार पत्रों में आ रहा है इसको जापान और भारत में मिलकर बनाएं यह बात मैं करके आया था। जापान और उसके लिए Joint Task Force बना दी गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो यह नई सोच नहीं है हर चीज को यह दिखाना किसी चीज की आप पैकेजिंग करा के, नया कागज ऊपर चढ़ा के original product नहीं बनती देश को यह समझना बहुत जरूरी है। बाकी वो कहें कि वो देश में बनेगा, जाहिर है जब देश में एफडीआई आएगी। किसी भी देश में तो वो, जो विदेशी निवेशक यहां आकर कारखाना लगाएगा वो Made in India ही होगा और Made for India ही होगा और जब निर्यात होगा वो भारत से ही निर्यात होगा। चाहे वो जापान वाली कार बनती हैं यहां पर, दक्षिण कोरिया की कार बनती है, पांच लाख गाड़ियां तो यूरोप को निर्यात की जाती हैं, वो Made in India के नाम से जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसी नई सोच नहीं दिखी जिसको इतना जोर से गर्जना के साथ कहा गया, और बार–बार दोहराया गया। जानकर लोग हैरान हो गए होंगे कि भारत आज तक कुछ नहीं बना पाया, भारत में कुछ बनता नहीं था। भारत इतनी बड़ी शक्ति है। INS Kolkatta जिसका उदघाटन करने गए थे वो भी भारत में ही बना था। उनके 15 और 16 के भाषण में भी विरोधाभास है।

तीसरी बात सबको इस बात पर दुःख भी होगा और तकलीफ भी होगी कि 2014 में यह महसूस करते हैं चर्चा करने की, सफाई एवं शौचालयों की प्रधानमंत्री ने उस पर टिप्पणी की, कोई आपत्ति नहीं है। निर्मल भारत अभियान देश में चल रहा है जिसको Rural Development Ministry देश में चला रहा है। वो हर गांव में, हर घर में शौचालय बनाने की बात करता है, निर्मल भारत अभियान उसमें बजट से राशि दी जाती है। लगभग 4300 करोड़ उसमें दिया गया जो हमने अंतरिम बजट में दिया था। प्रधानमंत्री ने इस निर्मल भारत अभियान का कोई जिक्र नहीं किया। या तो जानबूझ कर नहीं किया या जिसने कागज तैयार किए उन्होंने अपना होम वर्क ठीक नहीं किया और कोताही कर इन्होंने सांसदों को और कारपोरेटस को कहा है शौचालय बनाने के लिए स्कूलों में। स्कूलों में शौचालय बनाने की सुविधा और बजट की राशि सर्व शिक्षा अभियान में है। मुझे हैरानगी है कि देश के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं पता, उनके गुजरात को भी इस दिशा में राशि जाती है। निर्मल भारत अभियान के लिए इन्होंने एक रूपया नहीं बढ़ाया किसी ने रोका नहीं था। अगर सही अर्थ में इतनी गंभीरता थी, जब बजट पेश किया था तो उसको दो

गुना कर देते, है कोई इसका उत्तर। उद्योगपतियों को कहना कि आप बना दें, सांसदों को कहना आप बना दो। आपने प्रधानमंत्री के रूप में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया, इसकी बजट में राशि क्यों नहीं बढ़ाई। इसमें सीधी–सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। और यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं मैं हर विषय में नहीं जाना चाहता। योजना आयोग एक अहम बात है देश के लिए और उसकी एक तरफा घोषणा करना, बिना कोई सोच के, बिना किसी और माडल के, वो चिन्ता का विषय था ।

यह प्रश्न हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि यह प्रधानमंत्री का भाषण है किसी आम व्यक्ति का नहीं, चुनाव का भाषण नहीं है, लाल किले की प्राचीर से है, पूरा देश एवं पूरा विश्व सुनता है, इसलिए उसमें गंभीरता, गहराई और जिम्मेवारी सब आवश्यक है यह सब गैरहाजिर पाए गए।

एक प्रश्न पर कि इसी मंच से पूर्व वित्त मंत्री श्री चिदंबरम ने कहा था कि योजना आयोग में बदलाव होना चाहिए, श्री आनन्द शर्मा ने कहा कि वित्तमंत्री योजना आयोग के साथ मिलकर काम करते थे और कोई प्रस्तावना हमारी सरकार की नहीं थी। सरकार का एक तरीका होता है यदि कोई चीज बदली जाती है तो एक कैबिनेट नोट होता हे उसमें गंभीरता होती है, इस प्रकार से निर्णय नहीं होते हैं। मैंने आप से एक निवेदन किया है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि योजना आयोग की रूप रेखा बदली जानी चाहिए उन्होंने आदेश दिया था–15 पेज का नोट है। आज के प्रधानमंत्री को उस 15 पेज के नोट के बारे में बताना चाहिए था और सारे मुख्यमंत्रियों को भेजना चाहिए था उनके सुझाव लेने चाहिए थे और उसके बाद एनडीसी की बैठक बुलानी चाहिए थी।

On another question that Mr. Chidambaram also wanted the Planning Commission in a New Avatar, Shri Sharma said that is what I have said. The restructuring or new avatar, I have told you in my opening remarks that Dy. Chairman of Planning Commission had prepared a 15 page note and sent the same to the Prime Minister. That document is available. Shri Sharma said there is a big difference between restructuring and dismantling.

On another question as to how the Congress sees the calling off the Secretary level talks between Pakistan and India, Shri Sharma said let me amplify it. There has to be consistency and coherent policy in engaging with Pakistan. We cannot change history or geography; we have to accept the existence of a neighbor with whom India has tense and difficult relationship for historical reasons. BJP and Narendra Modi Ji in opposition had taken an extreme view virtually castigating UPA even for any contact. I would like to say that the composite dialogue process between India and Pakistan was suspended and frozen after the Mumbai terror attack and the composite dialogue was never restored by the UPA government. It did not mean

that we were not talking but we never restored the dialogue Now Shri Narendra Modi Ji and his government has taken a decision. The country is absolutely in dark because the functioning of the government is opaque as I have said there is no clarity. What has been discussed in two meetings between the PM of Pakistan and the PM of India is not known to anyone of us. This has never been shared even with parliament. If a decision was taken to have talks at this level when there were constant violations of ceasefire, escalation of terror attacks, tension on the border, then what was the understanding? There has to be an understanding as the basis to have the talks at the Foreign Secretary level. The PM and the government must share that understanding on the basis of which they agreed to talks in the first place. Main issue is not of calling off, the main issue was of switching on the dialogue process, there has to be some understanding. It is not something. Even if you take a small decision to go somewhere in Delhi, you will plan about it. Here you are going to talk with Pakistan. What was the motivation? What was the understanding and assurance? That must be shared with the country. Secondly, the PM and the government had two earlier occasions – one was the attitude of Pakistan state when it comes to bringing to justice the perpetrators of Mumbai terror attack including Hafiz Sayeed. His exoneration was one such serious occasion, this was happening. The PM was in Kargil - Good - but at the same time when he was speaking in Kargil, there was a big terror attack in Kashmir where our six jawans were killed. There was no reaction then. It raises many questions and frankly speaking we will appreciate if the government takes the country into confidence, takes the opposition into confidence about these matters and what development, assurances and understanding made Shri Narendra Modi decide that there should be a dialogue at such high level. We do not know, we are not in government. What assurance Nawaz Shareif had given and whether those assurances were violated. What was the understanding reached?

On the question of the stand of the Congress on Pakistan High Commissioner for meeting the leaders of the separatist group, Shri Sharma said this is objectionable. India has always objected and disapproved but at the same time recall is something which the government has to decide. The larger issue here is that as the preparations were being made for a dialogue between the Foreign Secretaries Pakistan forcefully put Kashmir on the top of the agenda. All the actions which I have said - there is the defined pattern. That is why I am repeating myself what was the understanding reached because when we talk of understanding, did Nawaz Shareif assure PM Narendra Modi that Pakistan establishment I am using the word 'establishment' very cautiously - this means Pakistani army and those elements who are supported of militant outfits are on board for the restoration of dialogue at a high level with India.

एक अन्य प्रश्न पर कि क्या बिना भारत सरकार की स्वीकृति के क्या यह संभव है कि अलगाववादी मिल सकता है, श्री शर्मा ने कहा कि आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यह वो कारगिल युद्ध के बाद भी मिलते थे भारत ने सदा इस पर अपनी आपत्ति जताई है। भारत ने सदा कहा है कि हम इनकी पहचान नहीं करते, वहां के नुमाइंदे हैं, कश्मीर के लोगों की नुमाईदंगी करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, एक संगठन है, अलगाववादी है, वो अपनी बात रखते हैं वो बात अलग है। जहां तक भारत सरकार एवं भारत देश का प्रश्न है, हमने इनको कभी स्वीकार नहीं किया।

Shri Sharma said we have never accepted because in a democracy it is the people of Kashmir who elect their government, who elect their MPs they vote. Hurriyat is neither representative of Kashmiri people nor democratic organization. Therefore, they are not authorized to engage in any manner when it comes to such complex issues. My question was very simple – Hurriyat is a fragmented organization and when the PM of India was in Kargil and the big terror attack was there in the same state Capital in Srinagar. There was no reaction similarly when there was the exoneration or clean chit to Hafiz Sayeed, we were quiet and I have linked three things.

On the question that it has been said by Pakistan side that the UPA government did not provide enough evidence in the form of voice samples to complete the trial in 26/11, Shri Sharma said what was required to be communicated and to be shared has been shared. It is the sincerity of Pakistan state which is in question. Whether they want to punish the perpetrators who have been supported and it is very well known why elements within the establishment, security establishment, who Pakistan chooses to refer as non state actors, but India has never accepted that terminology.

On the question of the Congress party over the fact that despite the meeting called off, Pakistan High Commissioner is going ahead with the meeting, Shri Sharma said Pakistan has a known policy viz-a-viz this particular issue and India and Pakistan have over the years tried to engage each other in a constructive manner to resolve the vexing problem. India has made it clear that Kashmir is an integral part of the Republic of India. The State of Kashmir is not there for any territorial negotiations. The only issue which we have is of terror, militancy, violence which finds support from elements within the Pakistani establishment which Pakistan must end. That would be in its own interest and for the regional peace, security and stability.

On the question of the Congress party on Chinese incursions, Shri Sharma said these are sensitive matters. First we have to get details and let the government

officially comment on it for us to respond because when it comes to issues of national security, defence, we always take a very careful and considered view and we also looked at what the facts are and to recheck the position and facts as on ground, then we will come up with the informed comment on this matter.

On the question of the AK Antony report, Shri Sharma said I am not privy. I know as much as you know about the report because the report has been submitted. The CWC will discuss the report which has been submitted. First it has to be discussed and its recommendations or findings taken on board by the party leadership and then we will share our views. I am afraid I have not been informed of the date but am sure the CWC will meet and discuss the report.

On a question of the reaction of the Congress party on a movie being released on 27th August "Kaum De Heere" to depict the assassins of former Prime Minister Smt. Indira Gandhi as the 'gems of community', whether the Congress party will ask for the ban, Shri Sharma said this is the for the government and the concerned authority to see that how serious this would be and its repercussions and fall out. Indira Gandhi was not only the PM of India; her leadership was acknowledged by all including her opponents and the rest of the world. She led India to great victories. There are many achievements during her Prime Ministership and she is martyr for the people of India. Any distortion of history, any eulogizing of assassins is something which is reprehensible, unacceptable and there are bodies, boards which have to take a view, give the certification, give the permission and they must take serious note of it. After losing thousands of lives and not of blood for years in the province of Punjab, we are happy that we have been able to restore peace, order and stability in Punjab. Nothing should be done to vitiate that environment and once again take away peace and security away. That is our concern.

एक अन्य प्रश्न पर कि एनडीए के शासनकाल में एल.के. आडवाणी ने दो बार अलगावादियों से बातचीत की थी, श्री शर्मा ने कहा कि इस विषय में भारत और पाकिस्तान किसी भी विषय पर बात करते हैं वो अलग बात है पर भारत के अन्दरूनी मामलों में पाकिस्तान दखल अंदाजी ना करे। मैंने पहले भी कहा है कि वाजपेयी जी के समय में ये मिलते रहते थे और बातचीत होती रहती थी। पर हुर्रियत के बारे में हमारे विचार भी स्पष्ट हैं और मैंने आज भी कहा है कि वो जम्मू–कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह हमारी सदा से पोजीशन रही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं।

(Tom Vadakkan)
Secretary
Communication Deptt.